

दिल्ली में बिजली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

वर्ष 2002 से

- उपभोक्ताओं की संख्या में करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जोकि 24.51 लाख से बढ़कर 42 लाख हो गई है।
- बिजली की मांग में करीब 100 प्रतिशत (2879 मेगावाट से 5642 मेगावाट) की बढ़ोतरी हुई है।
- दिल्ली डिस्कॉमस् तकरीबन 99 प्रतिशत बिजली की खरीद केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों से करती है।
- बिजली खरीद की कीमतों में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसकी कीमत पर डिस्कॉमस् का कोई नियंत्रण नहीं है।
- खुदरा टैरिफ में सिर्फ 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
- नॉन कॉस्ट रिफ्लेक्टिव रिटेल टैरिफ ने भावी प्राप्ति परिसम्पत्ति (रेग्युलेंटरी असेट) पर काफी ज्यादा असर डाला जो कि 19,500 करोड़ रुपये हो गई है जो दिल्ली डिस्कॉमस् के आपरेशनस् के निरंतरता पर असर डाल रहा है।

तुलनात्मक टैरिफ

दिल्ली में बिजली की दरें देश के अन्य मेट्रो और एनसीआर के अन्य शहरों से सस्ती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में नियमित रूप से कम से कम 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है जो कि मौसम और बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

हाल में डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद डीजल संचालित पावर बैकअप जनरेटर से इस्तेमाल होने वाली बिजली का न्यूनतम खर्चा 15 रुपये प्रति यूनिट है। दिल्ली के उपभोक्ता अपने पड़ोसी इलाके और शहरों की तुलना में औसतन काफी कम बिजली का भुगतान करते हैं।

दिल्ली बनाम अन्य महानगर

यूनिट्स/ माह	दिल्ली	कोलकाता	बंगलुरु	मुंबई
200	2.7*	5.6	3.9	4.3

दिल्ली बनाम अन्य राज्य

यूनिट्स/ माह	दिल्ली	मध्यप्रदेश	राजस्थान	तमिलनाडु
200	2.7*	4.8	4.8	4.0

दिल्ली बनाम एनसीआर

यूनिट्स/ माह	दिल्ली	गुडगांव/ फरीदाबाद	नोएडा
200	2.7*	4.9	3.5

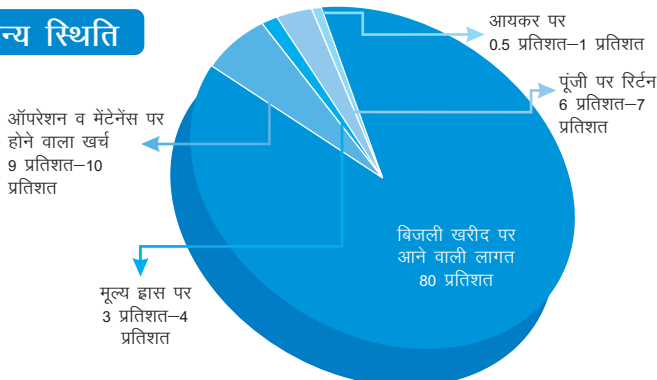
*200 यूनिट्स तक प्रति यूनिट 1 रुपये की सरकारी सब्सिडी शामिल

बिजली लागत के घटक

कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के नहीं मिलने की वजह से दिल्ली डिस्कॉम के रेवेन्यु (डीईआरसी द्वारा स्वीकृत) अपने आपरेटिंग और अन्य दूसरे खर्चों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। डिस्कॉम का तकरीबन 80 प्रतिशत रेवेन्यु बिजली की खरीद यानी पावर परचेज में चला जाता है जो अनियंत्रित है। लेकिन बीआरपीएल के मामले में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत है। पावर परचेज कॉस्ट और इंटररेस्ट कॉस्ट में वृद्धि का असर खर्च पर पड़ा है। साल 2012-13 के कुल रेवेन्यु की तुलना में व्यय 115 प्रतिशत रहा।

- बीआरपीएल का 100 प्रतिशत रेवेन्यु बिजली की खरीद और इंटररेस्ट कॉस्ट में चला जाता है। डिस्कॉमस् कॉस्ट एंव किसी तरह के रिटर्न को रिकवर् नहीं कर पा रही है।
- वितरण कंपनियां (डिस्कॉमस) देश के विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से बिजली की खरीद कर दिल्ली में बिजली वितरण करती है।
- दिल्ली डिस्कॉमस् बिजली की तकरीबन सभी खरीद दीर्घकालिक पीपीए के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के उपक्रमों से करती है। जिसके रेट केंद्र और राज्य के रेग्युलेटरस् निर्धारित करते हैं।
- दिल्ली डिस्कॉमस बिजली की खरीद विभिन्न राज्य सरकारों के उपक्रमों मसलन पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर आदि से करती है।

सामान्य स्थिति



स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स में 10 अप्रैल को छपा डीईआरसी विज्ञापन

वर्तमान स्थिति

